https://doir.coffice.gov.in/eFile/?x=...jXZTmtJWLnw8F2UoZPqnE

फा.सं.जेड-14014/2/2020-जीसी (ई-3010062)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 14.09.2020

**कार्यालय-ज्ञापन**

विषय: **अगस्त, 2020 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के प्रमुख कार्यकलापों का मासिक सार।**

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 एवं 11.10.2018 के पत्रांक 1/26/1/2018-कैब. के संदर्भ में और अगस्त, 2020 के लिए भूमि संसाधन विभाग के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

**(अर्जुन राणा)**

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

**सेवा में,**

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

**प्रतिलिपि प्रेषित:-**

1) भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2) भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3) भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान राचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4) उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5) सभी सचिव, भारत सरकार।
6) निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7) तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

**प्रतिलिपि सूचनार्थः**

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव।

भूमि संसाधन विभाग द्वारा अगस्त, 2020 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक सार

सचिव (भूमि संसाधन विभाग) की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2020 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि संसाधन विभाग में एक समिति का गठन किया गया है जिसका कार्य एक ओर वास्तविक कृषकों/खेतिहरों को केन्द्रीय सरकार की स्कीमों के लाभों को प्रदान करने और दूसरी ओर भू-स्वामियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भूमि पट्टा पर भावी कार्यनीति का सुझाव देना है।

भूमि संसाधन विभाग ने 14.08.2020 को 28 राज्यों के साथ वीडियो कोन्फरेंसिंग (वेबेक्स) के माध्यम से डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा की थी।

विश्व बैंक दल ने सचिव (भूमि संसाधन) के साथ वेबेक्स के माध्यम से दो बार क्रमशः 24.08.2020 और 31.08.2020 को बात की और आरईडबल्यूएआरडी के सहभागी राज्यों के साथ आरईडबल्यूएआरडी परियोजना के तहत की गई प्रगति और भावी कार्य योजना पर विचार-विमर्श किया। भूमि संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी की स्थिति का मूल्यांकन भी किया।

24.08.2020 से 31.08.2020 तक, विश्व बैंक दल ने आरईडबल्यूएआरडी परियोजना पर तृतीय मिशन का संचालन किया। इस मिशन ने सहभागी राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वेबेक्स बैठक की थी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत अब तक कुल 6382 {8214 (स्वीकृत)- 1832 (राज्यों को हस्तांतरित)} परियोजनाओं में से 4400 परियोजनाएं पूरी की गईं हैं। 2020-21 के दौरान अगस्त, 2020 में 2000 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में 100 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत 2020-21 दौरान 238.65 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में 11.64 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

*****